<u>अनुलग्नक</u>

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय की प्रमुख गतिविधियों का मासिक सार : जुलाई, 2023

I. स्वच्छ भारत मिशन

i. सभी 4,715 शहरों/कस्बों को ओडीएफ (खुले में शौच मुक्त) घोषित किया गया है, जिनमें से 4,355 शहरों को तृतीय पक्ष सत्यापन के माध्यम से प्रमाणित किया गया है, 3,547 शहरों को ओडीएफ+, 1191 शहरों को ओडीएफ++ और 14 शहरों (इंदौर, सूरत, नई दिल्ली नगर पालिका परिषद (एनडीएमसी), तिरूपति, चंडीगढ़, नवी मुंबई, विजयवाड़ा, हैदराबाद, ग्रेटर विशाखापत्तनम, कराड, पंचगनी, भोपाल, बारामती और मैसूर) को वॉटर+ के रूप में प्रमाणित किया गया है।

ii. 3,326 से अधिक शहरों में 67,407 शौचालय "एसबीएम शौचालय" के नाम से गूगल मानचित्र पर लाइव हैं।

iii. स्वच्छता ऐप एक ऐसे महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में उभरा है जो नागरिकों को सक्षम बनाने की दिशा में कार्यरत है ताकि उनकी शिकायतों का संबंधित नगर निगम द्वारा समाधान किया जा सके। स्वच्छता ऐप के कुल 2.08 करोड़ उपयोगकर्ता हैं, जिन्होंने 2.55 करोड़ शिकायतें पोस्ट की हैं, जिनमें से 2.39 करोड़ शिकायतों का समाधान किया गया है, जिनमें से 94% से अधिक का समाधान किया जा चुका है।

iv. जीएफसी 2022 का परिणाम 01 अक्टूबर 2022 को स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार समारोह 2022 के भाग के रूप में घोषित किया गया था। कचरा मुक्त शहरों (जीएफसी) के लिए स्टार रेटिंग प्रोटोकॉल के तहत 7-स्टार प्रमाणन वाले शहरों की संख्या 1 है, 5-स्टार प्रमाणन वाले शहरों की संख्या 11 है, 3-स्टार प्रमाणन वाले शहरों की संख्या 199 है और 1-स्टार प्रमाणन वाले शहरों की संख्या 234 है।

v. एसबीएम-यू 2.0 की योजना और कार्यान्वयन पर एक समीक्षा-सह-कार्यशाला 10.07.2023 को आयोजित की गई थी। माननीय आवासन और शहरी कार्य मंत्री ने उत्कृष्टता केंद्र, इंदौर में प्रशिक्षण कार्यक्रम, स्वच्छता ज्ञान भागीदार निर्देशिका और स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 टूलकिट के शुभारंभ की घोषणा की।

vi. माननीय मंत्री (आवासन और शहरी कार्य) ने 10 जुलाई, 2023 को स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के तहत स्वच्छ सर्वेक्षण (एसएस) - 2024 के 9वें संस्करण के लिए टूलकिट लॉन्च किया। टूलकिट में विशेष रूप से स्कूलों में स्वच्छता और

अपशिष्ट प्रबंधन, मिशन लाइफ से स्वच्छता और अपशिष्ट प्रबंधन इको-सिस्टम में एसएचजी की भागीदारी (एनयूएलएम के साथ अभिसरण) से संबंधित संकेतक शामिल किए गए हैं। शहरों में खुले में पेशाब करने को नियंत्रित करने के लिए, एसएस 2024 में पीले धब्बों को एक संकेतक के रूप में जोड़ा गया है।

II. स्मार्ट सिटी मिशन (एससीएम)

i. 1,79,205 करोड़ रू. की 8,023 परियोजनाएं चल रही हैं, जिनमें से 1,08,793 करोड़ रू. की 5,975 परियोजनाएं पहले ही पूर्ण की जा चुकी हैं।

ii. जुलाई माह में 1,110 करोड़ रुपये की 117 अतिरिक्त परियोजनाएं पूर्ण की गई हैं।

iii. आईटीडीपी इंडिया के सहयोग से स्मार्ट सिटीज मिशन, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा 'फ्रीडम2वॉकसाइकिलरन' अभियान का शुभारंभ किया गया था। एफ2डब्ल्यूसीआर अभियान 100 स्मार्ट शहरों के अतिरिक्त अन्य शहरों में सिटी मार्गदर्शकों (लीडरों) में पैदल चलने, साइकिल चलाने और दौड़ने को बढ़ावा देने के लिए हर तिमाही में 45 दिनों के लिए कार्यान्वित किया जाता है। वर्तमान में, **3 जून से 17 जुलाई 2023** तक की दूसरी तिमाही चल रही है। दूसरी तिमाही हाल ही में पूरी हुई, जो 45 दिनों तक चली और इस दौरान **130 से अधिक प्रतिभागियों** ने भाग लिया और **देश भर के 25 से अधिक शहरों में 58,000 किमी से अधिक साइकिल चलाने, पैदल चलने और दौड़ने को दर्ज किया गया।**

iv. स्मार्ट सिटी मिशन ने लोगों के लिए साइकिल चलाने, पैदल चलने, व्यायाम करने और दोस्तों के साथ मेलजोल बढ़ाने के लिए सड़कों के दायरे को बढ़ा कर उन्हें एक सुरक्षित, खुशहाल और स्वस्थ सार्वजनिक स्थानों के रूप में सड़कों को नए तरीके से बनाने के लिए स्ट्रीट्स4पीपल और इंडियासाइकल्स4चेंज की शुरुआत की है।

v. स्मार्ट सिटी मिशन ने लोगों को स्मार्ट सिटी से जोड़ने के लिए 1 जनवरी से 30 जून 2023 तक 6 महीने लंबा एक कार्यक्रम अमृत उत्सव का आयोजन किया। हालांकि, जब अधिक शहरों ने इसमें भाग लिया और कार्यक्रम आयोजित किए हैं, तो **अमृत उत्सव की समय सीमा 31 जुलाई 2023 तक बढ़ा दी गई।** अब तक, 100 स्मार्ट शहरों ने आठ विषयों में से एक या अधिक (अर्थात् वोकल फॉर लोकल, देश की एकता (युनिटी बाय टेक), स्थायी विकास, आत्मनिर्भर भारत, समावेशी विकास, स्वास्थ्य और कल्याण, महिला और बाल सशक्तिकरण, स्वतंत्रता संग्राम) पर 200+ ऑनलाइन/ऑफ़लाइन कार्यक्रम आयोजित किए हैं, जिसमें 6,00,000 से अधिक नागरिकों ने सक्रिय रूप से भाग लिया।

vi. 04 जून 2023 को, अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम (ट्यूलिप) ने शुरू होने की तारीख से तीन वर्ष सफलतापूर्वक पूरे कर लिए हैं। इस कार्यक्रम के तहत, जुलाई, 2023 तक कई यूएलबी में लगभग 10,000 से अधिक इंटर्नशिप के अवसर प्रदान किए गए हैं।

vii. **मिशन में उल्लेखनीय प्रगति**

• **100 स्मार्ट शहरों में** साक्ष्य-आधारित स्मार्ट प्रशासन में शहरों की मदद के लिए एकीकृत कमान और नियंत्रण केंद्र (आईसीसीसी) संचालित किए गए हैं।

• दक्षता लाने के लिए निजी क्षेत्र के साथ सहयोग/साझेदारी की आवश्यकता को मानते हुए **178 पीपीपी परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं** और लगभग **6,752 करोड़ रुपये** के निवेश के साथ **55 परियोजनाएं पाइपलाइन में हैं।**

• **1,055 जीवंत सार्वजनिक स्थान** (नदी/झील के किनारे, पार्क और खेल के मैदान और पर्यटन स्थल) **परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं।**

• शहरों को अधिक रहने योग्य और सुस्थिर बनाने के लिए **1,149 वॉश परियोजनाएं और 571 स्मार्ट ऊर्जा परियोजनाएं** पूरी की गई हैं।

III. अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत)

i. आज की स्थिति के अनुसार, 77,640 करोड़ रू. की अनुमोदित कार्य योजना से अधिक 83,149 करोड़ रू. की लागत वाली परियोजनाओं के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) को मंजूरी दे दी गई है। कुछ राज्यों ने अपने अनुमोदित एसएएपी से अधिक परियोजनाएं आरंभ की हैं, जिसमें अतिरिक्त राशि राज्यों/यूएलबी द्वारा वहन की जाएगी। 39,614 करोड़ रुपये की 5,001 परियोजनाओं का कार्य पूर्ण किया चुका है और 43,070 करोड़ रुपये की 891 परियोजनाओं का कार्य प्रगति पर है। कुल मिलाकर, पूर्ण/चालू अमृत परियोजनाओं में लगभग 72,770 करोड़ रू. का वास्तविक कार्य किया गया है, जिसका अर्थ है कि लगभग 94% वास्तविक कार्य पूर्ण किया जा चुका है।

ii. अब तक, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को परियोजना कार्यान्वयन (पूर्ववर्ती जेएनएनयूआरएम की पात्र परियोजनाओं सहित), प्रशासनिक और कार्यालय व्यय (ए एंड ओई), सुधार प्रोत्साहन के लिए और 'अमृत शहरों में जीआईएस आधारित मास्टर प्लान बनाने और 25 चयनित शहरों में स्थानीय क्षेत्र योजना (एलएपी) और कस्बा नियोजन योजनाएं (टीपीएस)' पर उप-योजनाओं के तहत 39,460 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं।

IV. दीनदयाल अन्त्योदय योजना - राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम)

i. चालू वित्तीय वर्ष के जुलाई माह के दौरान 8,657 स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) का गठन किया गया है; 4,802 एसएचजी को परिक्रामी निधि दी गई है; व्यक्तिगत और सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना के लिए 9,867 लाभार्थियों को ऋण की सहायता प्रदान की गई और एसएचजी-बैंक लिंकेज कार्यक्रम के तहत एसएचजी को 14,848 ऋण दिए गए।

V. पीएम पथ विक्रेता आत्मनिर्भर निधि (पीएमस्वनिधि)

i. पीएम पथ विक्रेता आत्मनिर्भर निधि (पीएमस्वनिधि) के तहत 69,77,483आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिसके लिए 54,39,685 स्वीकृतियां दी गई हैं और 51,45,848 संवितरण किए गए हैं।

ii. जुलाई, 2023 माह के दौरान मिशन के तहत कुल 9.432 करोड़ रू. जारी किए गए हैं।

VI. प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई)/सबके लिए आवास (एचएफए)

i. स्थापना से अब तक, मिशन में 1.19 करोड़ आवासों को मंजूरी दी गई है, जिनमें से 112.30 लाख आवासों का निर्माण कार्य आरंभ किया गया है, जिनमें से 76.02 लाख आवास पूर्ण किए जा चुके हैं/सुपुर्द किए जा चुके हैं।

ii. जुलाई, 2023 माह के दौरान पीएमएवाई(यू) के तहत 1,102.99 करोड़ रू. जारी किए गए हैं ।

VII. आवास

i. नागालैंड, जो नियमों को अधिसूचित करने की प्रक्रिया में है, को छोड़कर सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने रेरा के तहत नियमों को अधिसूचित कर दिया है।

ii. *32* राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने भू-संपदा नियामक प्राधिकरण की स्थापना की है। *लद्दाख, मेघालय और सिक्किम ने प्राधिकरण स्थापित करने के लिए अभी तक नियमों को अधिसूचित नहीं किया है।*

iii. 28 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने भू-संपदा अपीलीय न्यायाधिकरण (नियमित-24, अंतरिम-04) की स्थापना की है *(अरुणाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, मेघालय, मिजोरम, सिक्किम और पश्चिम बंगाल स्थापित करने की प्रक्रिया में हैं)।*

iv. 30 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के नियामक प्राधिकरणों ने रेरा के प्रावधानों के तहत अपनी वेबसाइटें चालू कर दी हैं। *(अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर अपनी वेबसाइटों को चालू करने की प्रक्रिया में हैं)।*

v. देशभर में 1,09,012 भू-संपदा परियोजनाओं और 77,960 भू-संपदा एजेंटों का रेरा के तहत पंजीकरण किया गया है।

vi. देश में भू-संपदा नियामक प्राधिकरणों द्वारा 1,11,374 शिकायतों का निपटान किया गया है। जुलाई, 2023 माह के दौरान 156 परियोजनाएं और 96 एजेंट पंजीकृत किए गए हैं।

***